उभरती अर्थव्यवस्था में कौशल विकास का महत्व: भारत के संदर्भ में

डा॰ डा॰ जय श्री भारद्वाज, एसोसिएट प्रोफेसर अर्थशास्त्र विभाग, आगरा कॉलेज आगरा ।

डॉ डा॰ शरद चंद्र ,एसोसिएट प्रोफेसर अर्थशास्त्र विभाग, आगरा कॉलेज आगरा।

Abstract : किसी भी देश के आर्थिक विकास और सामाजिक विकास के लिये ज्ञान के साथ-साथ कौशल भी महत्वपूर्ण है। विश्व की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में वही देश आगे हैं जिन्होंने कौशल का उच्च स्तर प्राप्त कर लिया है। कौशल की आवश्यकता को यहाँ वर्तमान सन्दर्भ सरकार ने काफी गम्भीरता से न सिर्फ महसूस किया है, वरन इसके लिये आवश्यक कदम भी उठाये हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.वी.वाई) देश के करोड़ों युवाओं को रोजगार मुहैया कराने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। इसका मूल चरित्र आजाद भारत के संस्कार पुरुष महात्मा गाँधी के सपनों के अनुरूप है। गाँधी जी ने हुनरमंद होने की पुरजोर पैरवी की थी। कौशल विकास कार्यक्रम के लिये मुख्य रूप से युवाओं पर ही जोर होता है। इस मामले में भारत अच्छी स्थिति में है क्योंकि हमारे पास लगभग 60 करोड़ 50 लाख लोग 25 साल से कम उम्र के हैं।

शब्द कुंजी – कौशल विकास, उद्यमशीलता, आर्थिक विकास, जनसंख्या, तकनीकी व रोजगारपरक शिक्षा, वैश्विक मंदी, मेक इन इंडिया, युवा जनसंख्या, अर्थव्यवस्था

किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए शिक्षा और कौशल विकास दो प्रेरक बल हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिन देशों ने कौशल का उच्च स्तर प्राप्त कर लिया है, वे देश उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मुख्य चुनौतियों से निपटने में सक्षम हैं। किसी भी देश में आर्थिक विकास कार्यक्रम में मुख्यतः युवाओं की भागीदारी पर जोर दिया जाता है। सौभाग्यवश हमारा देश इस मामले में अच्छी स्थिति में है। भारत विश्व के सबसे अधिक युवा राष्ट्रों में से एक है। यहाँ की कुल जनसंख्या में से 62 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या रोजगार करने वाले (15 से 59 वर्ष) की है और कुल आबादी के 54 प्रतिशत से अधिक 25 वर्ष से कम आयु के लोग हैं। अगले दशक में 15 से 59 आयु वर्ग की आबादी के और बढ़ने की उम्मीद है, जबकि अमेरिका, यूरोप और जापान जैसे विकसित देशों में यह औसतन 45 से 49 वर्ष की आयु के होंगे। परंतु हमारी अर्थव्यवस्था इससे तभी लाभान्वित होगी जब हमारे देश की युवा पीढ़ी स्वस्थ, शिक्षित एवं कुशल होगी।

आज शिक्षा पद्धंति स्तरीय होनी चाहिए जिससे छात्रो में आधारभूत क्षमता, योग्यता और कौशल का विकास किया जा सके। आज शिक्षा को सैद्धांतिक पाठ्यक्रमों की दलदल से निकालकर मजबूत व्यवसायिक आधार प्रदान करने की आवश्यकता है। अतः आवश्यक है कि शिक्षा के क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन किए जाएँ, न केवल बाहरी आधारभूत

संरचना को, बल्कि भीतरी स्तर पर विभिन्न अनुशासनों, विषयों को भी बदला जाये। बाज़ार, उद्योग, कारपोरेट जगत और समाज की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए नए विषय जोड़े जाएं, ताकि दक्ष और कुशल छात्र तैयार हो सकें। साथ ही पारम्परिक रूप से विकसित लघु और कुटीर उद्योगों से सम्बन्धित प्रशिक्षण, कौशल आदि को पाठ्यक्रमों में शामिल कर उसको अत्याधुनिक तकनीकी से जोड़कर नई शक्ल में ढालने की जरूरत है ताकि देश से पलायन करने वाले युवा इसके हिस्सेदार बनें और अधिक से अधिक रोजगार का सृजन हो सके।

वर्तमान में शिक्षा में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं, उसमें तकनीकी और रोज़गारपरक शिक्षा का प्रसार व विस्तार प्रमुख है।

तकनीकी शिक्षा के बिना विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। इस सन्दर्भ में पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम का यह कथन बहुत प्रासंगिक है "किसी भी राष्ट्र की खुशहाली और प्रगति तकनीकी और रोज़गारपरक शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। गरीबी और बेरोज़गारी इसकी प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। भारत में पर्याप्त मानवीय शक्ति है, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के द्वारा इस शक्ति का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है। "

स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक भारत सरकार इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के द्वारा जनशक्ति को आर्थिक रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिये देश के विभिन्न कोनो मे तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों की स्थापना की गई है जो कि व्यावसायिक शिक्षा की दिशा में राष्ट्र की महत्वपूर्ण पहल है। परंतु यह चिन्तनीय है कि आज की शिक्षा प्रणाली कुशल रोज़गार के लिए जनशक्ति का निर्माण करने की अपनी भूमिका ठीक प्रकार नहीं निभा पा रही है। परिणामस्वरूप कौशल सम्बन्धी बाजार की आवश्यकताओं और रोज़गार चाहने वाली जनशक्ति के बीच खाई बढ़ती ही जा रही है। ज्ञान आयोग के अनुसार भारत के लगभग 57 प्रतिशत युवा रोज़गार पाने की योग्यता नहीं रखते हैं। यह आंकड़े हमारी शिक्षा की निम्न गुणवत्ता को प्रदर्शित करते हैं।

इस सन्दर्भ में अगर हम जर्मनी की बात करें तो वैश्विक मंदी के दौर में भी जर्मनी की अर्थव्यवस्था मजबूती से टिकी रही। जर्मनी की इस सफलता में बहुत बड़ा योगदान 'स्किल डेवलपमेंट' का है। वहाँ एक खास उम्र के बाद विद्यार्थी ज्यादा वक्त अपरेटिसशिप में गुजारते हैं। स्कूलों में 'वोकेशनल ट्रेनिंग' व 'अपरेटिसशिप'

के दौरान वे स्किल्स सीखते हैं। देश में 'मैन्युफैक्चरिंग' उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्किल लोगों का पुनः तैयार किया जाता है मजबूत निर्यात के दम पर भारी संख्या में रोज़गार पैदा करने वाले देश जर्मनी का रोज़गार आंकड़ा हैरान कर देने वाला है। जर्मनी यूरोप की अकेली अर्थव्यवस्था रही है, जहाँ मंदी के समय सबसे कम नौकरियों की कटौती हुई। एक दशक के अन्दर बेरोजगारी घटकर आठ (5.9 प्रतिशत) रह गई।

वैश्विक निर्यात में जर्मनी की हिस्सेदारी 9 प्रतिशत है और यह 1.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच चुका है। चौंकाने वाली बात है कि 2015 में जर्मनी में दस लाख शरणार्थी पहुँचे, इसके बावजूद भी इसका अर्थव्यवस्था अन्य यूरोपीय देशों के मुकाबले मजबूत रही। अतः जर्मनी एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। मेक इन इंडिया व स्किल डेवलपमेंट में भारत के लिये जर्मनी का सहयोग अहम है। इस संदर्भ में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व जर्मनी के चांसलर एंजेला के बीच वार्ता हुई है।

स्पष्ट है कि आज के समय मे किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिये शिक्षा के साथ-साथ कौशल विकास भी अत्यंत आवश्यक है। भारत जैसे देश के सन्दर्भ में यह और भी महत्वपूर्ण है, जहाँ हर वर्ष लगभग 13 मिलियन युवा रोज़गार बाज़ार में प्रवेश करते हैं। मांग पक्ष पर विचार करें तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा किये गये अंतराल के बारे में कराये गये अध्ययन से पता चलता है कि 2022 तक 24 उच्च विकास क्षेत्रों के लिये सत्तत बुद्धिमान 10.9 करोड़ मानव संस्थानों की आवश्यकता पड़ेगी। भविष्य में अनुमानित कुशल श्रम बल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 2022 तक 500 मिलियन सुट्ट कुशल श्रम बल तैयार करने का लक्ष्य रखा है। अब तक देश में कुल श्रम बल में से केवल 4.69 प्रतिशत लोगों को ही औपचारिक कौशल प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। अमेरिका में यह 52 प्रतिशत व दक्षिण कोरिया में यह 96 प्रतिशत है। कौशल विकास के कार्यों में तीव्रता लाने के लिये सरकार ने 2014 में अलग से "कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय" गठन किया है। मंत्रालय का लक्ष्य भारत के युवाओं को दीर्घकालीन रोज़गार से लेकर स्वरोजगार तक नाना भाँति के आजीविका मार्गों तक पहुँच कायम करने में सक्षम बनाने के लिये अपेक्षित कौशल विकास प्रदान करना था।

2015 में एक महत्वाकांक्षी कौशल विकास कार्यक्रम "प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना" (पी एम के वी वाई) का शुभारम्भ किया गया था। बाद में उच्च गुणवत्ता के प्रशिक्षण के जरिये रोजगार के अवसरों के बढ़ाने पर अधिक ध्यान केन्द्रित करते हुए 10 मिलियन युवाओं को कुशल बनाने के लक्ष्य के साथ पिछले 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर इस योजना को चार वर्षों के लिये अनुमोदित कर दिया है। इस योजना के अन्तर्गत मुख्य रूप से श्रम बाजार में पहली बार प्रवेश करने वाले लोगों पर और होगा और मुख्यतः कक्षा 10 व 12 के दौरान स्कूल छोड़ने वाले छात्रों पर ध्यान केन्द्रित किया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण और मूल्यांकन शुल्क पूर्ण रूप से सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य कुशल श्रमबल के कौशल, ज्ञान और महत्वाकांक्षा को रोजगार के अवसर तैयार करने और बाजार की माँग जोड़ना है। सरकारी और निजी क्षेत्र के उच्चतर शिक्षा संस्थानों, स्कूलों, आई.टी.आई. और उद्यमशीलता विकास केन्द्रों में 3050 परियोजनाओं की मदद से 15 लाख छात्रों को ऑनलाइन उद्यमशीलता शिक्षा प्रदान की जायेगी। 2014 से 2017 की अवधि में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या में 24 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। मई 2014 में यह संस्थान 10750 थे जो मई 2017 में बढ़कर 13,353 हो गए। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों की दाखिल में इज़ाफा हुआ। वर्ष 2013-14 में विद्यार्थियों की संख्या 17.80 लाख थी जो 2016-17 में बढ़कर 22.4 लाख हो गई। ग्रामीण युवाओं की कौशल सम्बन्धी आवश्यकताओं की अलग से पूर्ति करने के लिये रोजगार नियोजन से जुड़ा

कौशल विकास कार्यक्रम, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डी.डी.यू-जी.के.वाई) है, जिसमें 2016-17 में 1,62,586 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण दिया उनमें से 84,900 को रोजगार प्राप्त हो गया है।

वर्तमान मौजूदा आँकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अन्तर्गत 17.95 लाख लोगों को प्रशिक्षण किया गया। मंत्री परिषद ने हाल ही में अगले चार वर्षों अप्रैल 2016 से मार्च 2020 तक 60 लाख व्यक्तियों को नया प्रशिक्षण देने के लिये और औपचारिक कौशल प्राप्त कर चुके लगभग 40 लाख लोगों को प्रमाण पत्र देने के लिये 12,000 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है। इस योजना के अन्तर्गत अधिगृहित संस्थानों में कौशल प्रशिक्षण ले रहे अभ्यर्थियों को 8000 प्रति अभ्यर्थी औसत पारिश्रमिक प्रदान किया जायेगा।

वर्तमान सरकार ने कौशल विकास एवं उद्यमिता राष्ट्रीय नीति 2015 को प्रथम एकीकृत नीति के तौर पर मंजूरी दी। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य उच्च मानकों सहित तेजी के साथ बड़े पैमाने पर कौशल प्रदान करते हुये सुनिश्चितिकरण की व्यवस्था करना और उद्यमिता पर आधारित नवाचार संस्कृति को बढ़ावा देना है। जो देश में नागरिकों को स्थायी आजीविका को सुनिश्चित करने के लिये धन व रोजगार का सृजन कर सके | इस योजना का उद्देश्य 2022 तक 42 करोड़ भारतीय युवा शक्ति को उद्योगों की मांग के अनुरूप प्रशिक्षित कर रोजगार के लिये तैयार करना है | देश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये मुम्बई आई.आई.टी., चेन्नई आई.आई.टी., अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एवं बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की सहायता ली जायेगी |

युवाओं के अतिरिक्त दूसरा क्षेत्र महिला प्रशिक्षण का है | अध्ययन बताते हैं कि यदि आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के बराबर हो जाए तो भारत की जी.डी.पी. में 27 प्रतिशत तक की आशातीत बढ़ोतरी हो सकती है | किन्तु ये भागीदारी बिना उचित कौशल प्रशिक्षण के सम्भव नहीं है | इसलिए योजनाओं के अन्तर्गत महिलाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है | 1450 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और सामान्य आई.टी.आई. 1004 महिला विंग के माध्यम से महिलाओं को व्यावासिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है | राष्ट्रीय व्यावासिक प्रशिक्षण परिषद में सामान्य आई.टी.आई. संस्थानों में 30 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिये आरक्षित करने की सिफारिश की गयी है |नक्सलवाद से प्रभावित 34 जिलों में कौशल विकास सुविधायें विकसित करने के लिये हर जिले में आई.टी.आई. संस्थान और दो कौशल विकास केन्द्र स्थापित किये गये हैं ताकि इस क्षेत्र में युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाये जिससे नक्सलवाद पर अंकुश लग सके |

लगभग चालीस करोड़ भारतीय युवाओं को प्रशिक्षित बनाने की महत्वाकांक्षी योजना भारत का भाग्य बदल सकती है | वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के शब्दों में "यदि चीन दुनिया की फैक्ट्री बन सकता है तो भारत विश्व में मानव संसाधन प्रदान करने वाली धुरी क्यों नहीं बन सकता?आज भारत ने विश्व में सबसे तेजी से विकास कर रही

अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी पहचान बना ली है | आशा है कि भारत शीघ्र ही दुनिया की तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सम्मिलित हो जायेगा और वर्ष 2020 तक भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विनिर्माण केन्द्र बन जायेगा |

संदर्भ सूत्र :

1. भारतीय आधुनिक शिक्षा, त्रैमासिक एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली, अंक जुलाई-अक्टूबर 2007.

2. भारत 2017, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

3. योजना, सितम्बर 2009, योजना अगस्त 2015

4. कुरुक्षेत्र, अप्रैल 2015, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली

5. Employment News, Vol. XLII, 2-8 September 2017

6. कौशल विकास एवं उद्यमितामंत्रालय www.skilldevelopment.in

7. जनसत्ता, मुखपृष्ठ/रविवारीय स्तम्भ, 25 जनवरी 2015

8. पी.टी.आई., 18 अप्रैल 2015

9. The Hindu, 27 Feb. 2015

10. कुरुक्षेत्र, सितम्बर 2017, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली

लेखक विवरण

डॉ. जयश्री भारद्वाज, एसोसिएट प्रोफेसर, आगरा कॉलेज, आगरा

डॉ. शरद भारद्वाज, एसोसिएट प्रोफेसर, आगरा कॉलेज, आगरा